बजट का सार—एक संक्षिप्त परिचर्चा

डॉ0 अर्चना कुमारी वर्मा

प्रवक्ता—अर्थशास्त्र

महाराणा प्रताप शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान

पी0जी0 कालेज नगहरा, अम्बेडकरनगर उ0प्र0

प्रस्तावना— बजट पद्धति संसाधनो की उपलब्धता का अनुमान लगाने और फिर उन्हें एक पूर्व निश्चित प्राथमिकता के अनुसार किसी संगठन के विभिन्न कार्यकलापों के लिए आवंटित करने की एक प्रक्रिया है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में संसद के दोनो सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्राक्कलित प्राप्तियों एवं व्ययों का विवरण रखवाएगा जिसे इस भाग में 'वार्षिक वित्तीय विवरण' कहा गया है। इस वार्षिक वित्तीय विवरण को ही 'आम बजट' कहा जाता है। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार, प्रत्येक राज्य सरकार का राज्य का 'वार्षिक वित्तीय विवरण' तैयार करती है, जिसे राज्य सरकार का बजट कहा जाता है।

सरकार की बजटीय नीति राजकोषीय नीति का महत्वपूर्ण भाग होती है। सरकार के बजटीय नीति में सरकार के सभी कार्यक्रमों एवं नीतियों को शामिल किया जाता है। इसके राजस्व पक्ष में कर प्राप्तियों एवं अन्य प्राप्तियों के रूप में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों को दिखाया जाता है। तथा इसके व्यय पक्ष में उपभोग व्यय, निवेश व्यय तथा हस्तांतरण भुगतानों के रूप में सरकार के अनुमानित व्यय को प्रकट किया जाता है।

1920—21 के दौरान ब्रिटिश रेलवे अर्थशास्त्री 'विलियम एकवर्थ' की अध्यक्षता मे 10 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। इसी एकवर्थ समिति का गठन किया गया। इसी एकवर्थ समिति की सिफारिशों को आधार बनाकर 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया। इसके पीछे तर्क दिया गया कि रेलवे एक उद्यम है, जो लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्य करती है।

भारत का पहला बजट 18 फरवरी 1860 के जेम्स विल्सन द्वारा लार्ड कैनिंग के शासन काल में प्रस्तुत किया गया,जबकि स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवम्बर 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री आर0 के0 षणमुखम चेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया।

केन्द्रीय बजट में तीन लगातार वर्षो की प्रप्तियों और व्यय का विवरण होता है, जो इस प्रकार व्यवस्थित होता है—

1) आगामी वित्तीय वर्ष के लिये बजट अनुमान

2) चालू वित्तीय वर्ष के लिये संशोधित अनुमान

3) पिछले वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्तियाँ तथा व्यय

बजट एक महत्वपूर्ण नियोजन का साधन है, जो लोकनीतियों के कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करता है। यह प्रस्तावित व्यय को भविष्य की गतिविधियों से जोड़ता है। यह सरकार में कार्यपालिका द्वारा किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण कार्य है। यह योजना प्रबन्धन, नियंत्रण और जवाबदेही के एक साधन के रूप मे कार्य करता है। लोक धन एक प्रमुख संसाधन है। जो सरकार का भंडार है। इसका व्यय सावधानी से करने की जरूरत है। बजट उन गतिविधियों से, जिनके लिए धन आवंटित किया जाता है, लोगो को अधिक लाभ प्रदान करने का साधन है। इसीलिए बजटीय प्रणाली प्रबंधन लोक वित्त का एक प्रमुख घटक है। यह इकाई सरकार के संदर्भ में बजट की अवधारणा का परिचय देती है, और शिक्षार्थियों को इसके उद्देश्यों, विशेषताओं, कार्यो और प्रकारो से उन्मुख करती है।

बजटः अवधारणा– बजट एक विवरण प्रक्रिया है, जिसमें आमतौर पर एक वर्ष की अवधि के लिए राजस्व और व्यय का पूर्वानुमान होता है। यह एक व्यापक कार्य योजना है, जो सरकार द्वारा निर्धारित नीतिगत उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दिशा प्रदान करती है।

सरकार बजट एक दस्तावेज है, जो एक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के प्रस्तावित राजस्व और व्यय को प्रस्तुत करता है, जिसे संसद विधानमंडल द्वारा पारित किया जाता है और राष्ट्रपति या मुख्य कार्यकारी द्वारा अनुमोदित किया जाता है। देश के वित्त मंत्री आमतौर बजट पेश करते हैं।

बजट शब्द का उद्भव एक पुराने फ्रांसीसी शब्द, बौगेट (Bougette) से हुई है, जिसका अर्थ है 'लेदर बैग'। यह लैटिन शब्द 'लेदर बैग' या गॉलिश मूल (Gaulish origin) के 'नैप्सैक से लिया गया है। सर रॉबर्ट वालपोल ने पहली बार ग्रेट ब्रिटेन मे बजट और राजकोषीय नीति प्रस्तुत करने की प्रक्रिया शुरू की।

भारत मे 'बजट' शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में नहीं किया गया है, हालंकि इस प्रक्रिया को आमतौर पर बजटिंग कहा जाता है। प्रयुक्त शब्द 'वार्षिक वित्तीय विवरण है। यह बजट के कई दस्तावेजो में से एक है, जिसे वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। बजट आमतौर पर हर साल फरवरी के आखिरी हफ्ते में पेश किया जाता है।

एक सरकारी बजट एक वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार के अपेक्षिक व्यय और इन व्ययों के वित्तपोषण के स्रोतों का एक विवरण है।

एक बजट निम्नलिखित के सम्बंध में जानकारी प्रदान करता है।

1) वर्तमान वर्ष से सम्बंधित योजनाएं, कार्यक्रम, परियोजनाएं,व्यवस्थाएं और गतिविधियां और आगामी वर्ष के लिए प्रस्ताव

2) वित्त के स्रोत

3) पिछले वर्ष की प्राप्तियाँ और व्यय

4) सरकार की विभिन्न एजेंसियों के कार्य संपादन से सम्बंधित आर्थिक और लेखा डेटा।

उद्देश्य– सरकारी बजट के 1 अप्रैल से शुरू होने वाले और अगले वर्ष के 31 मार्च के समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय को दर्शाने वाले विवरण के रूप में परिभाषित किया गया है।

सरकार सभी स्तरो पर प्रस्तावित गतिविधियों के बारे में निर्णय लेती है और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। बजट के साधन के माध्यम से धन आवंटित किया जाता है, जिसे विधायिकों संसद, नागरिक, निकायों आदि द्वारा पारित किया जाता है।

एक बजट में अर्थव्यवस्था को सरकार द्वारा निर्धारित की गई दिशा के अनुसार चलाने की शक्ति होती है। यह महत्वपूर्ण आर्थिक नीति साधन है, जिसके द्वारा सरकार की नीतियों को आवश्यक क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जाता है। जो निम्नलिखित है।

(1) **जवावदेही–** सरकारी बजट नागरिकों को यह अधिकार देता है कि वे धन के प्रभावी और कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए लोक संस्थानों को जवाबदेह ठहरा सके इसलिए, यह लोगों में विश्वास पैदा करता है कि धन का उपयोग विनियोजित उद्देश्यो के किया जा रहा है।

(2) **परिणाम–** अपनी प्रक्रियाओं के माध्यम से बजट का उद्देश्य बजट में पूर्व–निर्धारित परिणामों के लिए सम्बंधित अधिकारियों/प्रबंधको की जवाबदेही को भी तय करना है। यह उनकी सफलता का आकलन करने के लिए योजनाओं और परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करता है।

(3) **दक्षता और मितव्ययता–** बजट प्रक्रिया मे यह सुनिश्चित किया जाता है कि एकत्रित राजस्व और आवंटित संसाधन किफायती तरीके से खर्च किये जा रहे है।

(4) **निष्पादन मूल्यांकन–** कानून द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि सरकार की अपने कार्यों के लिए जवाबदेही हो। बजट के माध्यम से कार्य संपादन मूल्यांकन यह सुनिश्चित करता है कि खर्च किये गये धन से निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग सरकारों को नीतियो और प्रशासन से सम्बंधित कार्य संपादन का आकलन करने में मदद करती है।

(5) **संसाधनों का पुनः आवंटन–** पिछले कुछ वर्षो में, बजट प्रक्रिया के एक भाग के रूप में कार्य संपादन मूल्यांकन अगले वित्तीय वर्ष के बजट अनुमानो को तैयार करने का आधार रहा है। इस प्रकार, यह अभ्यास सरकार को सामाजिक कल्याण के लिए संसाधनों को पुनः आवंटिकृत करने में मदद करता है।

(6) **आय का पुनर्वितरण–** सरकार का बजट और उसकी नीतियाँ धन को वांछित दिशा में व्यय करने में मद्द करती है। यह समाज के संतुलित आर्थिक विकास के कुछ स्तर को प्राप्त करने के लिए आय के पुर्नवितरण के लिये कार्य करता है। यह एक विशिष्ट समूह या कुछ वस्तुओं पर कराधान के स्तर को बढ़ा या घटा सकता है।

(7) आर्थिक स्थिरता– एक सरकारी बजट का उद्देश्य देश में अपनी राजस्व और व्यय नीति का उपयोग करके स्थायी आर्थिक स्थिति बनाये रखना है।

(8) आर्थिक विकास– अंत में, सरकार धन आवंटित करके और विशेष रूप से आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे में निवेश करके आर्थिक विकास को गति देने का प्रयास करती है।

बजट सार में बजट की सर्म्पूण बातों को इस ढ़ग से दर्शाया गया होता है, ताकि इन्हें असानी से समझा जा सके। इस दस्तावेज में भारत सरकार की प्राप्तियों और व्यय के साथ–साथ राजकोषीय घाटा (FD), राजस्व घाटा (RD) ,प्रभावी राजस्व घाटा (ERD) और प्रथमिक घाटा (PD),दर्शाया जाता है।

ग्राफ एवं इन्फो–ग्राफिक्स के माध्यम से प्राप्तियों के स्त्रोतों और उनके व्यय का चित्रात्मक व्यौरा दिया जाता है। इसके अलावा, इस दस्तावेज में राज्यों और विधान सभा मण्डल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को हस्तांतरित किए गये संसाधनों, कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए किये गये आवटंनों का सारांश और घाटे के वित्तपोषण के स्त्रोतो से संबन्धित व्यौरा शामिल होता है। राजकोषीय घाटा, कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर है। राजकोषीय घाटा सरकार के कुल उधारीआवश्यकता को दर्शाता है। राजस्व घाटे का अर्थ राजस्व व्यय का राजस्व प्राप्तियों से अधिक होना है। प्रभावी राजस्व घाटा, राजस्व घाटे और पूंजीगत प्राप्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान के बीच का अंतर है। प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगियों को घटाकर निकाला जाता है। प्रभावी पूंजीगत व्यय का अर्थ, पूंजीगत व्यय और पूंजीगत प्राप्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान का जोंड़े है।

इस दस्तावेज में वर्णित प्राप्तियां और व्यय, प्राप्ति बजट (अनुबंध–3) और व्यय की रूपरेखा दस्तावेज (विवरण संख्या–17) में दिये गये मिलान सम्बन्धी विवरण में यथा स्पष्ट प्राप्तियो और वसूलियो के निवल है। तथा संशोधित अनुमान 2024–25 में कुल व्यय रू0 47,16,487 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है। इसकी तुलना में वित्त वर्ष 2023–24 के वास्तविक कुल व्यय रू0 44,43,447 करोड़ था। वित्त वर्ष 2023–24 के वास्तविक में रू0 9,49,195 करोड़ की तुलना में संशोधित अनुमान 2024–25 में कुल पूंजीगत व्यय रू0 10,18,429 करोड़ होने अनुमान लगाया गया है।

बजट अनुमान 2025–26 में कुल व्यय रू0 50,65,345 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है, जिसका कुल पूंजीगत व्यय रू0 15,48,282 करोड़ है। बजट अनुमान 2025–26 में कुल राज्यों की अंतरित कुल संसाधन रू0 25,01,284 करोड़ है जिसमें राज्य का हिस्सा अनुदान ऋण और केन्द्रीय प्रयोजित योजनाओ के अंतर्गत निर्गमन आदि शामिल है। जो वित्त वर्ष 2023–24 के वास्तविक में रू0 4,91,668 करोड़ की वृद्धि को दर्शाता है।

1–राजस्व प्राप्तियां	2– कर राजस्व
3– कर भिन्न राजस्व	4– पूंजी प्राप्तियां
5– ऋणो की वसूली	6– अन्य प्राप्तियां
7–उधार और अन्य देयताए	8– कुल प्राप्तियां (1+4)
9– कुल व्यय (10+13)	10– राजस्व खाते पर जिसमें से
11– व्याज भुगतान	12– पूंजी खाते के सृजन हेतु सहायता अनुदान
13–पूंजी खाते पर	14– प्रभावी पूंजी व्यय (12+13)
15– राजस्व घाटा (10–7)	16– प्रभावी राजस्व घाटा (15–12)

17– राजकोषीय घाटा [9–(1+5+6)]

18–प्राथमिक घाटा (17–11)

सरकारी बजट की विशेषताएँ–

(1) व्यापकता– एक बजट, वास्तव में, एक वित्तीय योजना है, एक निश्चित अवधि के लिए सरकार की पूर्ण मैट्रिक आवश्यकताओ को अग्रिम रूप से निर्धारित करती है। और ऐसा करने में, अनुमानित आय के साथ व्यय की जरूरतों को संतुलित करती है। एक बजट में व्यापकता का आधार एक्य का नियम होता है, जिसके अनुसार एक ही कोष होना चाहिए और एकत्र किये गये सभी धन का समेकित कोष में रखा जाना चाहिए। यह दक्षता से सरकारी लेनदेन को सरल करता है।

(2) संतुलित– राजस्व और व्यय को संतुलित करना एक आवश्यक सिद्धांत है, हालॉकि वर्तमान लोकतंत्र में, सरकारें वित्त पोषण, लोकऋण और उधार के माध्यम से लोगों की जरूरतों को पूरा करती है, और संतुलित बजट को महत्व नहीं देती है।

(3) बजट अनुमान नकद आधार पर होते है– बजट में उस धन को शामिल किया जाता है, जो बजट की अवधि के दौरान प्राप्त या खर्च किया जाता है।

(4) बजट चक्र– बजट चक्र मे शामिल है।

(1) लोगो की सामाजिक आर्थिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अनुमान तैयार करना।

(2) रिकार्ड किये गये व्यय डेटा के सम्बंध में अनुमानो से जाँच करना।

(3) पिछले वर्ष के सरकार की आय का मूल्यांकन।

(4) बजट एजेंसियो द्वारा बजट तैयार करना।

(5) विधायी निकाय द्वारा बजट विधेयक का अधिनियमन

(6) प्रशासनिक निकायों द्वारा विनियोजित धन के अनुसार बजट का कार्यान्वयन।

(5) वार्षिकता– अधिकांश बजट वार्षिक वित्तीय योजनाये होती है जिनमें नियमित अंतराल पर मतदान की आवश्यकता होती है। हालॉकि, यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें एक बजट तैयार किया जा रहा है, जबकि दूसरा कार्यान्वित किया जा रहा है।

(6) त्रुटि का नियम– बजट की अवधि वार्षिक होने के कारण, इसका तात्पर्य है कि वित्तीय वर्ष के अंत में कोई भी अव्ययित शेष राशि समाप्त हो जाती है और सरकार द्वारा खर्च नही की जा सकती है। नये सिरे के प्रस्तावों और अनुमोदनों की जरूरत होती है।

(7) पूर्व–निर्धारित उद्देश्य– सुस्थापित और परिभाषित उद्देश्यों के बिना बजट तैयार नहीं किया जा सकता है।

(8) लचीलापन– कई मामलो में, परियोजनाओं को समय या लागत में वृद्धि, कच्चे माल की कीमत में वृद्धि आदि के कारण धन की कमी का सामना करना पड़ता है। चूकि बजट की वार्षिक अवधि होती है, परियोजनोओं के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक होने पर अधिक धन आवंटित करने के प्रावधान है, ताकि परिभाषित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

(9) सटीकता– बजट एक सटीक वार्षिक वित्तीय विवरण है, जो पिछले वर्ष में किये गये अनुमानों और व्यय की सटीकता पर आधारित है। बजट जहाँ तक सम्भव हो सटीक होना चाहिए। इसलिए बजट में लक्ष्यों को पहले तय किया है, ताकि अनुमान सटीकता के साथ तैयार किये जा सके जो अंततः विधायी निकायों द्वारा अनुमोदित होते है।

सरकारी बजट सिद्धांत– एक सरकारी बजट ठोस बजट और वित्तीय प्रबंधन के सिद्धांतो पर आधारित होता है जिससे इसकी विशेषताओं और कार्यो को कार्यो को निर्धारित किया जाता है, जो निम्नलिखित है–

1. व्यापकता– व्यापकता का तात्पर्य मुद्दो को निर्धारित करने, सभी जोखिम को समझाने और संस्थागत ढाचे में कमजोरियों का आकलन करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण से है, ताकि वांछित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। इसमे बजट विभाग बजट प्रक्रियाओ मे सुधार द्वारा सरकारी नीतियों को संरेखित और निर्धारित करता है। व्यापकता का अर्थ यह भी है कि बजट में सरकार के सभी राजकोषीय कार्यो को शामिल करना चाहिए। साथ मे यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वित्तीय निहितार्थ वाले नीतिगत निर्णय बजट की कठिन सीमाओ की पृष्ठिभूमि और अन्य माँगो को ध्यान में रखकर किये गये है। किसी विशेष नीति उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सबसे उपयुक्त नीति साधन के चयन करने का तात्पर्य है वर्तमान और पूँजीगत व्यय निर्णयो को संतुलित करना।

2. अनुशासन– यह आवश्यक है कि बजट प्रक्रिया में मितव्ययिता के साथ–2 अनुशासन का भी पालन किया जाये और यह कि बजट केवल उन संसाधनो को समाहित करे जो सरकारी नीतियों को लागू करने के लिए आवश्यक है।

3. वैधता– एक बजट की पुष्टि विधायिका द्वारा की जाती है। उन नीतियो से सहमत होने के लिए जिन पर शुरू में सहमति हुई थी वैधता का यह भी अर्थ है कि निर्णय लेने वालों के पास निर्णय लेने के लिए सभी प्रासंगिक जानकारी हो।

4. जवाबदेही पारदर्शिता और सूचना –जवाबदेही और पारदर्शिता के बीच अर्न्तसम्बन्ध है। इनके लिए अपेक्षित है कि प्रत्याशित परिणामो और लागतो के साथ जो निर्णय लिये ये सुलभ स्पष्ट और व्यापक समुदाय के लिए संप्रेर्षित हो पारदर्शिता के लिए यह भी आवश्यक है कि निर्णय लेने वालो के पास निर्णय लेने के लिए सभी प्रासंगिक जानकारी हो।

5. पूर्वानुमेयता– विभागीय एजेंसियों द्वारा तैयार लिये गये अनुमानों के एकत्रीकरण द्वारा बजट तैयार किया जाता है। नीतियों और कार्यक्रमों के कुशल और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पूर्वानुमेयता महत्वपूर्ण है। एक स्थिर समष्टिगत और कार्यनीति के लिए और मौजूद नीति के कार्यक्रमों और परियोजनाओ के वित्त पोषण के लिए धन की सामजिक आवश्यकता होती है।

आर्थिक सहयोग और विकास सगंठन द्वारा निर्धारित सिद्धांत– ओ ई सी डी OECD Organisation for Economic Cooperation & Development) ने बजटीय प्रशासन वार्षिक बजट तैयार करने की प्रक्रिया इसमे कार्यान्वयन की निगरानी और लोक लक्ष्यों के साथ इसमे संरेखण की सुनिश्चित

करने के लिए इस सिद्धान्तों को प्रस्तावित किया। ये बजट के पूरे विस्तार में अच्छी प्रक्रिया का संक्षिप्त अवलोकन प्रदान करते हैं। इसका उददेश्य नागरिको के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए बजट प्रणालियों के डिजाइन कार्यान्वयन और सुधार पर व्यावहारिक र्मागदर्शन देना है।

दस सिद्धांत निम्न प्रकार है—

1. राजकोषीय नीति द्वारा निर्धारित स्पष्ट विश्वसनीय और पूर्वानुमेय सीमाओं के भीतर बजट को तैयार करना।

2. सरकार की मध्यम अवधि की कार्यनीति की प्राथमिकताओं के साथ बजट को संरेखित करना।

3. पूँजी बजट की रूपरेखा को राष्ट्रीय विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिए मितव्यपिता और सामंजस्य के साथ डिजाइन करना।

4. बजट दस्तावेजों को सार्वजनिक डोमेन मे रखकर सभी तक उनकी पहुँच को सुगम बनाना ।

5. बजटीय बहस मे नागरिको की भागीदारी को बढ़ावा देना।

6. विधायी निकाय को लोक धन का विश्वसनीय और सटीक लेखा तैयार करना और प्रस्तुत करना।

7. बजट का कार्यान्वयन सक्रिय रूप से योजनावद्ध प्रबंधित और निगरानी पूर्ण करना।

8. बजट प्रक्रिया का कार्य संपादन मूल्याकंन और पैसे के मूल्य के घटकों के साथ एकीकरण।

9. वित्तीय जोखिम का संज्ञान प्राप्त करना उनकी विवेकपूर्ण तरीके से पहचान आजकल और स्वतंत्र लेखा परीक्षा के माध्यम से बजटीय पूर्वानुमानों वित्तीय योंजनाओं और बजटीय कार्यान्वयन की सत्यनिष्ठा और गुणवत्ता को बढ़ावा देना।

10. कठिन गुणवत्ता आश्वासन और स्वतंत्र लेखा परीक्षा के माध्यम से बजटीय पूर्वानुमानों वित्तीय योजनाओं और बजटीय कार्यान्वयन की सत्यनिष्ठा और गुणवत्ता को बढ़ावा देना।

बजट के प्रकार– बजट न केवल आय और व्यय का विवरण है, बल्कि एक कार्य योजना भी है जो कार्यक्रमों और विभिन्न गतिविधियों और उनके संचालन को इंगित करता है। समय के अनुसार इसका स्वरूप बदल रहा है। बजट विभिन्न प्रकार के होते हैं जिन पर हम चर्चा करेगें, जो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं:—

1) योजना प्रोग्रामिंग और बजट प्रणाली (Planning Programming & Budgeting Systems –

यह बजट के साथ योजना और प्रोग्रामिंग को एकीकृत करता है। यह उद्देश्यों को परिभाषित करता है और विकल्पों का चुनाव, उनकी पहचान और मूल्यांकन, कार्य करता है। यह बजट आउटपुट के साथ प्रत्येक कार्यक्रम और गतिविधि की प्रभावशीलता का आंकलन करने का प्रयास करता है। यह कार्य क्रमों के माध्यम से योजनाओं को बजट के साथ एकीकृत करता है। इसका उपयोग (USA) में किया गया था, लेकिन भारत सहित कई देशों में इसे ठीक से लागू नहीं किया गया था।

शून्य आधारित बजट– इसके लिए संगठनों को शुरू में अपनी गतिविधियों का आकलन करके यह सिद्ध करने की जरूरत है कि वे उचित है। फिर जिन गतिविधियों को शुरू किया जाता है, तदानुसार धन का प्राथमिकता करण किया जाना है। एक तरह से सभी बजट अनुरोधों की

आधार शून्य से शुरू करना है, यानि आरम्भ से और सभी प्रस्तावित गतिविधियाँ जिनके लिए धन माँगा जाता है उन्हे उचित सिद्ध करने की जरूरत है और कार्यक्रमों को संपादन के आधार पर रैंक किया जाता है।

बजट के लिए कुछ समकालीन दृष्टिकोण है जैसे कि जेन्डर–आधारित परिणाम और हरा या बजट, जिसकी चर्चा इस पाठ्यक्रम की इकाई 7 में की जायेगी।

राजस्व बजट– एक राजस्व बजट में सभी वर्तमान प्राप्तियाँ शामिल होती है। जैसे कराधान, लोक उद्यमों का अधिशेष और लोक व्यय। सरकार की राजस्व प्राप्तियों में करों और अन्य प्राप्तियों के माध्यम में आय और ऐसे राजस्व से किये गये व्यय की मदें शामिल हैं।

राजस्व प्राप्तियाँ– राजस्व प्राप्तियों मे सरकार द्वारा, बिना किसी दायित्व या सम्पत्ति में कमी के, सभी स्रोतों से प्राप्त की गई आय शामिल है। राजस्व प्राप्तियों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है–कर राजस्व और गैर–कर राजस्व।

(क) कर राजस्व– कर राजस्व सरकार द्वारा अपने करों और शुल्कों के माध्यम से उत्पन्न और प्राप्त होने वाली आय है।

कर दो प्रकार के होते है–

1) प्रत्यक्ष कर (Direct Tax)**-** प्रत्यक्ष कर वे होते हैं, जिनका भुगतान एक व्यक्ति को करना पड़ता है और भुगतान का बोझ किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को नहीं सौंपा जा सकता है। इसका भुगतान न करना दण्डनीय अपराध है। प्रत्यक्ष करों के उदाहरण– आयकर, सम्पत्तिकर, निगमकर, सम्पत्ति शुल्क आदि।

2) अप्रत्यक्षकर (Indirect Tax)**-** अप्रत्यक्ष कर वह कर है जो वस्तुओं और सेवाओं पर लगाये जाते है, और जब इनका उपभोग करता है तो वे उसकी आय को प्रभावित करते है। प्रत्यक्ष करों के विपरीत अप्रत्यक्ष करों का बोझ किसी और पर हस्तातंरित किया जा सकता है।

उदाहरण– सीमा शुल्क, विक्री कर, सेवा कर आदि।

(ख) गैर–कानूनी राजस्व (Non Tax Revenue)**–** अन्य गैर कर स्त्रोतो से भी राजस्व की प्राप्तियाँ होती है।

गैर–कर राजस्व के स्त्रोत– फीस, दंड, लाभ, उपहार, अनुदान, विशेष मूल्यांकन शुल्क

(ग) राजस्व प्राप्तियाँ– राजस्व प्राप्तियों में केन्द्र द्वारा लगाये गये करो और अन्य शुल्कों की आय, सरकार द्वारा किये गए निवेश पर ब्याज और लाभांश सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओ के लिए शुल्क और अन्य प्राप्तियाँ शामिल है। ये सरकार को नगदी के प्राप्ति के स्त्रोत है।

राजस्व व्यय (Revenue Expenditure)**–** राजस्व व्यय वह व्यय है जो सरकारी विभागो के दिन प्रति दिन के प्रशासन और जनता को बुनियादी ढ़ाचा गति सेवाओ के प्रावधान के लिए किया जाता है। इसमें केन्द्र सरकार के विकास और गैर विकास व्यय भी शामिल है इस प्रकार, वह व्यय जिसमे कोई सम्पत्ति निर्माण नही होता है उसे राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है।

सरकार द्वारा किए गए कुछ व्यय जो राजस्व व्यय में शामिल है–

(1) वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग

(2) कृषि और औद्योगिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवाएं और विज्ञान पर अनुसंधान

(3) रक्षा और नागरिक प्रशासन

(4) निर्यात और विदेश मामले

(5) राज्य सरकारों को अनुदान

(6) पिछले वर्ष में किये गए ऋण ब्याज भुगतान

(7) सब्सिडी

पूंजीगत प्राप्तियाँ– पूंजीगत प्राप्तियाँ वे प्राप्तियाँ हैं जो देनदारी उत्पन्न करती है या सम्पत्तियों में कमी करती है। उधार, ऋण वसूली और सम्पत्ति विक्रय के माध्यम से धन जुटाया जाता है।

पूंजीगत प्राप्तियों के घटक– पूंजीगत प्राप्तियों के मुख्य घटक हैं।

(1) बाजार ऋण– बाजार ऋण सरकार द्वारा जनता से ब्रांड और प्रतिभूतियाँ जारी करके जुटाए जाते है।

(2) उधार– सरकार ट्रेजरी बिल बेचकर भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों से
उधार लेती है।

(3) विदेशी ऋण– सरकार विदेशो और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियो जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक आदि से ऋण और सहायता प्राप्त करती है।

(4) योजनाएँ– राष्ट्रीय बचत योजना भविष्य निधि आदि जैसी छोटी बचत योजनाओं से धन जुटाया जाता है।

(5) ऋण वसूली– पूंजीगत प्राप्तियों से राज्यो केंद्रशासित प्रदेशों और अन्य से ऋण वसूली शामिल है।

पूंजीगत व्यय– एक व्यय जिसके द्वारा व्यापक अवधि में सम्पत्ति उत्पन्न करने का प्रस्ताव है वह पूंजीगत व्यय है।

सरकारी बजट : कार्य– एक बजट लक्ष्यों और कार्यान्वयन को संरेखित करने के लिए सरकार की नीतियो के विवरण के रूप में कार्य करता है। बजट एक नीति वक्तव्य है। यह सरकार की नीति को निर्धारित करता है जिसके अन्तर्गत सरकार की परियोजनाओं, योजनाओं और गतिविधियों को प्राथमिकता से कार्यान्वित किया जाता है। कई सरकारें **'बजट नीति'** वक्तव्य नामक दस्तावेज प्रकाशित करती है। वार्षिक वित्तीय विवरण में रखे गये आइटम उन लक्ष्यो को इंगित करती है, जिन्हे सरकार प्राप्त करना चाहती है एक सरकारी बजट योजनाओ के द्वारा राजकोषीय नीति निर्धारित करने के लिए उपयोगी साधन के रूप में कार्य करता है।

सरकारी बजट के कार्य नीचे दिये गये है–

(1) योजना– बजट एक नियोजन का साधन है यह सरकारी कार्यो की योजना बनाने मे लोक प्रशासको की सहायता करता है बजट आगामी वर्ष में शुरू की जाने वाली परियोजनाओ और कार्यक्रमो के लिए व्यय की योजना निर्धारित करता है।

(2) जबावदेही– बजट जबावदेही के एक साधन के रूप में कार्य करता है यह धन स्वीकृत मदो और उद्देश्यो पर खर्च करने के लिए कार्यपालिका पर विधायी नियन्त्रण सुनिश्चित करता है।

(3) उत्तरदायित्व और नियन्त्रण– एक बजट बजटीय प्रक्रिया के माध्यम से जिम्मेदारी और प्रचलित नियंत्रण सुनिश्चित करता है। यह योजनाओं और उन्हें दक्षता और प्रभावशीलता के साथ लागू करने के साधन निर्धारित करता है। भारत में, संसद की विभिन्न वित्तीय समितियो द्वारा विधायी नियंत्रण सुनिश्चित किया जाता है।

(4) पूर्वानुमान– एक बजट पिछले बजट के आधार पर पूर्वानुमान करने मे मदद करता है। पूर्वानुमान सामाजिक आर्थिक विकास को प्राप्त करने के लिए सभी हित धारकों के कार्यो और लक्ष्यों पर विचार करता है।

(5) संचार– एक बजट विभिन्न गतिविधियों योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यन्वित और परिणामों पर जानकारी प्रसारित करके सम्प्रेषण के साधन के रूप में कार्य करता है बजट नागरिको और कर दाताओं के लिए शक्तिशाली माध्यम है जिसके द्वारा उन्हें विशिष्ट उद्देश्यों के लिए स्वीकृत राशि से अवगत कराया जाता है।

महत्व–

बजट आधुनिक राज्यों में राष्ट्र की आर्थिक नीति को संचालित और नियंत्रित करने के विशिष्ट साधनों में प्रमुख स्थान रखता है। यदि यह कहा जाये कि वर्तमान राज्यों का संचालन बजट के माध्यम से होता है तो इसमें कोई आयुक्ति न होगी। सरकार वजट की सहायता से अपना कार्य करती है। तथा सार्वजनिक आय के विभिन्न स्रोतो का अधिकतम सद्पयोग करने की योजना बनाती है। जो सरकार इस कार्य को जितनी अधिक क्षमता से करती है, वह अपने नागरिको की आर्थिक और भौतिक समृद्धि को उतनी ही तेजी से बढ़ाती है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्लैण्डस्टोन ने एक बार कहा था, " बजट केवल गणित के आंकड़े मात्र नहीं है, किंतु यह हजारों व्यक्तियो की समृद्धि विभिन्न वर्गो के पारस्परिक संबंधों तथा राज्यों की शक्ति का मूल है।"

द्वितीय विश्वयुद्ध से पूर्व बजट राज्य सरकारों के प्रशासन के लिए धन प्राप्त करने का साधन मात्र थे। किन्तु वर्तमान में बजट किसी राष्ट्र के आय–व्यय को संतुलित करने का ही कार्य नही करते हैं। अपितु वे अर्थव्यवस्था के विकास का साधन है, और नये आर्थिक चिन्तन और नूतन परीक्षणों का श्री गणेश करते है। इनमें सरकार की नीति एवं देश की आर्थिक परिस्थितियों प्रतिबिम्बित होती है। वस्तुतः सार्वजनिक वित्तीय प्रशासन का हृदय है– बजट जिसमें अनेक लिए धन निर्धारित किया जाता है। बजट किसी राष्ट्र की वित्तीय स्थिति के लिए दर्पण, दीपक और दिग्योतक यंत्र के तीन प्रकार के कार्य करता

है। जिस प्रकार दर्पण व्यक्ति के मुखाकृति को वास्तविक ‘रुप में प्रतिबिम्बित करता है, उसी प्रकार किसी देश का बजट अनुसरण किये जाने वाले वित्तीय पथ को आलोकित करता है। किंतु बजट का इसमें भी बड़ा कार्य उस दिशा को बताना है जिस दिशा की ओर राष्ट्र की अग्रसर होना है। नेहरु जी के शब्दो में–‘‘बजट को इस दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए कि देश में क्या करना है और किन लक्ष्यों को प्राप्त करना है।’’

बजट कई कारणों से प्रशासकों, विधायकों एक नागरिकों के लिए अत्यंत उपयोगी है। प्रशासन करने वाले सरकारी अधिकारी बजट की सहायता से ही विभागों का प्रशासन समुचित रीति से कर सकते है। बजट विधायको को देश की अर्थव्यवस्था पर पूरा नियंत्रण और अंकुश रखने का साधन प्रदान करता है। बजट नागरिको और कर दाताओं के लिए की अतीव उपयोगी है,क्योकि इससे नागरिको को यह पता चलता है कि सरकार का काम चलाने के लिए कितना रुपया व्यय किया जा रहा है। सरकार को किस स्त्रोत से कितनी आमदनी होती है और वह इस आमदनी का किस प्रकार व्यय करता हैं।

निष्कर्ष– यह वित्तीय योजना , नियंत्रण और निर्णय लेने के लिए के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो व्यक्ति व्यवसाय और सरकार के लिए आर्थिक विकास और स्थिरता सुनिश्चित करता है। यह वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने, खर्चो को व्यवस्थित करने और भविष्य के लिए बचत करने में मद्द करता है। एक अच्छी तरह से तैयार किया गया बजट वित्तीय और सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है।

व्यक्ति और व्यवसाय के लिए–

वित्तीय अनुशासन– बजट आपको अपनी आप और व्यय पर नजर रखने में मदद करता है, जिससे आप अनावश्यक खर्चो से बच सकते है।

लक्ष्य निर्धारण– यह भविष्य के लिए लक्ष्य निर्धारित करने और बचत करने में मदद करता है। जैसे कि– घर खरीदना, बच्चों की शिक्षा व व्यावसायिक निवेश।

निर्णय लेने में सहायता– यह एक योजना प्रदान करता है कि क्या खर्च करना सुरक्षित है और भविष्य के लिए कैसी योजना बनानी है।

सरकार के लिए–

आर्थिक नीति – सरकार के लिए, बजट देश के आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और आय असमानता को कम करने के लिए एक व्यापक वित्तीय योजना के रूप में कार्य करता है।

संसाधनों का आवंटन – यह कर राजस्व और व्यय का अनुमान लगाता है, जिससे सरकार को सार्वजनिक नीतियों और सेवाओं के लिए संसाधनों का प्रभावी ढ़ग से आवंटन करने में मदद मिलती है।

जवाब देही – यह सरकार के वित्तीय प्रदर्शन में पारदर्शिता और जबाव देही सुनिश्चित करता है।

नियोजित विकास – बजट वित्तीय योजना की संरचना लाता है और यह सुनिश्चित करता है कि संसाधन प्रभावी ढ़ग से आवंटित किये जाये।

जोखिम प्रबंधन – यह समस्याओं का पूर्वानुमान लगाने और गलत अनुमानों के कारण होने वाले संभावित नुकसान को कम करने में मदद करता है।

सकारात्मक प्रभाव – एक व्यवस्थित बजट लागत को कम कर सकता है, संघर्षों को कम कर सकता है और समग्र दक्षता में सुधार कर सकता है।

संदर्भ ग्रंथ–सूची

Buck.A.E (1929), A discussion of Budegeting Practice in the national state & Local Governments of the uni.

1. चक्रवर्ती, अभिषेक (21 सितम्बर 2016) । ''92 वर्षों से प्रस्तुत किया जा रहा रेल बजट, केन्द्रीय बजट में विलय''
2. www.indiabudget. gov. in | 3 फरवरी 2021 को पुनः प्राप्त
3. एन डी टी वी । प्रेस ट्रस्ट और इंडिया । 19 फरवरी 2016
4. Money,bhaskar.com | 25 मार्च 2019 को संग्रहीत
5. केन्द्रीय बजट का पुनरावलोकन Pib.nic.in. 6 मार्च 2021 का संस्करण
6. द इकोनॉमिक टाइम्स। 29 जून 2019
7. प्राप्ति बजट 2023–24 (pdf) 9 फरवरी 2023 को संग्रहीत
8. ब्रीफिंग, भारत (23 जुलाई 2024) ।''भारत का केन्द्रीय बजट 2024–25 प्रमुख घोषणाएँ
9. आर्थिक सर्वेक्षण 15 जनवरी 2023
10. https://www.gratoati.com. en2hi. Search. translate. goolen / literature-
11. Selections/goverment- budgeting/2003